Volume: 5 Issue: 4 Pages: 50-52

कोटा नगर में जीवन-गुणवत्ता का एक समग्र अध्ययन

[*1] कार्तिक मिश्रा एवं [2]डॉ. हमीद अहमद

[*1] शोधार्थी, भूगोल विभाग, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, झालावाड, कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत।

[2] प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, झालावाड, कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (QJIF): 8.4
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 15/March/2026
Accepted: 10/April/2026

***Corresponding Author**
कार्तिक मिश्रा
शोधार्थी, भूगोल विभाग, राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, झालावाड, कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत।

सारांश
शहरीकरण आधुनिक समाजों के सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जो ग्रामीण-आधारित संरचना से शहरी-औद्योगिक व्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाती है। भारत जैसे विकासशील देश में यह प्रक्रिया अवसरों और चुनौतियों—दोनों को जन्म देती है। प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के सर्वाधिक शहरीकृत नगर कोटा को अध्ययन-क्षेत्र बनाते हुए तीव्र शहरीकरण के जीवन-गुणवत्ता (Quality of Life) पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय तथा मानसिक-स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का समग्र विश्लेषण करता है। अध्ययन में जनगणना आँकड़ों, द्वितीयक सांख्यिकीय स्रोतों, नगर नियोजन दस्तावेज़ों तथा पर्यावरणीय सूचकों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि कोटा में शहरीकरण ने जहाँ एक ओर आर्थिक अवसरों, शिक्षा और अवसंरचना विकास को गति दी है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय क्षरण, मानसिक स्वास्थ्य संकट, एक-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की अस्थिरता तथा सामाजिक दबाव जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न की हैं। अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि सतत और समावेशी शहरी विकास के बिना जीवन-गुणवत्ता का संतुलित उन्नयन संभव नहीं है।

मुख्य शब्द: शहरीकरण, जीवन-गुणवत्ता, कोटा, प्रवासन, कोचिंग उद्योग, पर्यावरणीय क्षरण, मानसिक स्वास्थ्य

प्रस्तावना:

1. भूमिका

शहरीकरण को परंपरागत ग्रामीण समाज से आधुनिक शहरी-औद्योगिक समाज की ओर संक्रमण का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है। यह केवल जनसंख्या के स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आजीविका, सामाजिक संबंधों, पर्यावरण और जीवन-शैली में संरचनात्मक परिवर्तन को भी प्रतिबिंबित करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। भारत में यह प्रक्रिया ग्रामीण संकट से उत्पन्न धक्का कारकों तथा शहरी अवसरों से जुड़े आकर्षण कारकों—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार—के कारण तीव्र हो गई है।

राजस्थान, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, शहरीकरण की दृष्टि से तीव्र असमानताओं को प्रदर्शित करता है। इसी संदर्भ में कोटा नगर एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसने औद्योगिक नगर से शिक्षा-केंद्रित महानगर के रूप में तीव्र शहरी परिवर्तन का अनुभव किया है।

2. अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. कोटा में शहरीकरण की ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
2. प्रवासन-जनित शहरीकरण के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
3. तीव्र शहरी विस्तार के पर्यावरणीय परिणामों, विशेषकर चंबल नदी पर प्रभाव, का मूल्यांकन करना।
4. शहरी जीवन-गुणवत्ता पर मानसिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों की पड़ताल करना।
5. सतत शहरी विकास हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

3. अध्ययन क्षेत्र: राजस्थान में शहरीकरण एवं कोटा की स्थिति

1901 में राजस्थान की शहरी जनसंख्या मात्र 14.8 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 1.70 करोड़ हो गई। इसी अवधि में शहरीकरण का स्तर 14.41% से बढ़कर 24.87% हो गया। हालाँकि यह वृद्धि रैखिक नहीं

रही—महामारियों और ऐतिहासिक घटनाओं ने इसे प्रभावित किया। इसी राज्यीय परिप्रेक्ष्य में कोटा राजस्थान का सर्वाधिक शहरीकृत ज़िला बनकर उभरा। 2011 में कोटा में शहरीकरण का स्तर 60.3% रहा, जो जयपुर (52.4%) और अजमेर (40.1%) से भी अधिक है। यह दर्शाता है कि राज्य की शहरी जनसंख्या तेजी से **क्लास-I नगरों** की ओर केंद्रित हो रही है।

4. जनसांख्यिकीय परिवर्तन एवं नगरीय फैलाव

कोटा नगर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख शहरी केंद्र है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच नगर की जनसंख्या 6.94 लाख से बढ़कर 10.01 लाख हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः प्रवासन से प्रेरित रही। इस जनसंख्या दबाव के कारण नगर की भौतिक संरचना में भी मूलभूत परिवर्तन हुए। पारंपरिक दो-मंज़िला आवासीय स्वरूप के स्थान पर बहु-मंज़िला अपार्टमेंट संस्कृति का विकास हुआ। वर्ष 2000 से 2023 के बीच कोटा का निर्मित क्षेत्र 122% से अधिक बढ़ गया, जिससे कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा।

5. आर्थिक संरचना में परिवर्तन: औद्योगिक नगर से कोचिंग राजधानी तक

बीसवीं शताब्दी के मध्य तक कोटा एक औद्योगिक नगर था, जहाँ डीसीएम श्रीराम और चंबल फ़र्टिलाइज़र्स जैसे उद्योग प्रमुख थे। इन उद्योगों ने नगर की प्रारंभिक आर्थिक और अवसंरचनात्मक नींव रखी।

1980 के दशक के बाद कोटा में कोचिंग उद्योग का अभूतपूर्व उदय हुआ। 2020 तक यह उद्योग लगभग 12,000 करोड़ रुपये का हो गया और प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक विद्यार्थी आईआईटी-जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोटा आने लगे। इससे हॉस्टल, मैस, परिवहन, स्टेशनरी और छोटे व्यापारों का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ।

6. एक-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की अस्थिरता एवं वर्तमान संकट

कोचिंग उद्योग पर अत्यधिक निर्भरता ने कोटा की अर्थव्यवस्था को अत्यंत संवेदनशील बना दिया। कोविड-19 के बाद विद्यार्थियों की संख्या लगभग 50% घट गई, जिससे नगर को प्रतिवर्ष लगभग 1,500 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।

हॉस्टलों की अधिभोग दर 100% से गिरकर 40–60% रह गई। अनेक भवन *घोस्ट बिल्डिंग* में बदल गए और लिए गए ऋण एनपीए बनने लगे। यह संकट दर्शाता है कि बिना आर्थिक विविधीकरण के शहरी विकास दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं होता।

7. पर्यावरणीय प्रभाव: चंबल नदी संकट

कोटा का शहरीकरण चंबल नदी के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। नगर प्रतिदिन लगभग 312 एमएलडी अपशिष्ट जल उत्पन्न करता है, जबकि शोधन क्षमता अपर्याप्त है। 155–200 एमएलडी अशोधित जल सीधे नदी में प्रवाहित होता है।

इसके परिणामस्वरूप जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग (BOD) 9–14 mg/L तक पहुँच गई है, जो अनुमेय सीमा से कई गुना अधिक है। इससे जलीय जैव-विविधता में तीव्र गिरावट आई है और घड़ियाल तथा गंगा डॉल्फ़िन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियाँ प्रभावित हो रही हैं।

8. जीवन-गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या संकट

कोटा की जीवन-गुणवत्ता कोचिंग संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। विद्यार्थियों के लिए 16–18 घंटे का अध्ययन, सामाजिक अलगाव और निरंतर रैंकिंग ने नगर को प्रेशर कुकर बना दिया है।

2023 में 27 और 2024 में 16 विद्यार्थियों की आत्महत्या ने इस संकट को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। प्रशासन द्वारा कोटा केयर्स जैसे कार्यक्रम चलाए गए, किंतु प्रदर्शन-केंद्रित संस्कृति अभी भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है।

9. सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अपराध

राजस्थान में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात राष्ट्रीय मानकों से कम है। कोटा में पृथक जिला चिकित्सालय का अभाव तथा झुग्गी-बस्तियों में रहने वाली लगभग 32% शहरी आबादी के लिए स्वास्थ्य जोखिम अधिक हैं।

अपराध की दृष्टि से भी युवा, अस्थायी जनसंख्या की अधिकता ने महिला अपराध, आर्थिक अपराध और साइबर अपराध की आशंकाओं को बढ़ाया है।

10. भविष्य की दिशा: कोटा मास्टर प्लान 2031

कोटा मास्टर प्लान 2031 नगर के भविष्य के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत—

- नगरीय क्षेत्र का विस्तार 86,961 एकड़ तक,
- राणपुर और शंभूपुरा जैसे *ग्रोथ सेंटर*,
- हरित एवं मनोरंजन क्षेत्रों में चार गुना वृद्धि,
- आईटी पार्क, मेडिकल हब और ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष:

कोटा का शहरीकरण एक गहरे विरोधाभास को उजागर करता है। एक ओर यह नगर शिक्षा, साक्षरता और आर्थिक अवसरों का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरणीय क्षरण, मानसिक स्वास्थ्य संकट और आर्थिक अस्थिरता का उदाहरण भी है।

कोटा में जीवन-गुणवत्ता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि नगर किस प्रकार कोचिंग-आधारित एक-क्षेत्रीय मॉडल से हटकर विविध, पर्यावरण-अनुकूल और मानवीय शहरी तंत्र की ओर संक्रमण करता है। संतुलित, समावेशी और सतत शहरी नियोजन ही कोटा को दीर्घकालिक रूप से रहने योग्य नगर बना सकता है।

References

1. Bettencourt LMA, Lobo J, Helbing D, Kühnert C, West GB. Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2007; 104(17):7301–7306. https://doi.org/10.1073/pnas.0610172104
2. Boeing G, Church D, Hubbard H, Mickelson R, Rudis L, Stokes R. Using open data and open-source software to develop spatial indicators of urban design and transport features for achieving healthy and sustainable cities. Urban Analytics and City Science. 2022; 49(2):1-23. https://doi.org/10.1177/239980832210520
3. Census of India. Primary census abstract: Rajasthan. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, 1901–2011.
4. District Administration, Kota. Kota Cares: Mental health and student welfare initiatives. Government of Rajasthan, 2024.
5. Government of India. Smart Cities Mission: Statement & guidelines. Ministry of Housing and Urban Affairs, 2015.
6. Government of Rajasthan. Kota Master Plan 2031. Town Planning Department, Jaipur, 2023.
7. Government of Rajasthan. Economic survey of Rajasthan. Directorate of Economics and Statistics, Jaipur, 2023-2024.

8. Jean N, Burke M, Xie M, Davis WM, Lobell DB, Ermon S. Combining satellite imagery and machine learning to predict poverty. Science. 2016; 353(6301):790-794. https://doi.org/10.1126/science.aaf7894
9. National Crime Records Bureau. Crime in India 2022. Ministry of Home Affairs, Government of India, 2023.
10. National Crime Records Bureau. Accidental deaths & suicides in India. Ministry of Home Affairs, Government of India, 2024.
11. Rajasthan State Pollution Control Board. Water quality assessment of Chambal River (Kota stretch). Jaipur, 2023.
12. Singh J, Yadav H, Smarandache F. District level analysis of urbanization from rural-to-urban migration in Rajasthan state. *International Journal of Applied Mathematics.* 2009; 22(3):421-444.
13. Son G, Kim J, Lee S. Urban green spaces and quality of life: A systematic review. Sustainable Cities and Society, 2021; 67:102708. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102708
14. United Nations Department of Economic and Social Affairs. World urbanization prospects: The 2018 revision. United Nations, 2019.
15. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). World cities report 2020: The value of sustainable urbanization. UN-Habitat, 2020.
16. World Health Organization. Primary health care systems: Monitoring and evaluation framework. WHO Press, 2019.
17. Zou Z, Ergan S. Leveraging data-driven approaches to quantify the impact of construction projects on urban quality of life. Automation in Construction. 2019; 104:1-12. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.03.017